# झारखण्ड के राँची जिले के दिव्यांगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार में सरकारी एवं गैर सरकारी सस्थाओं की पहल

1. **डॉ. सलमा खातून, शोध-निर्देशिका, सहायक प्राध्यापक, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड**
2. **रंजू कुमारी, शोधार्थिनी, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, साई नाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड Email id - sharmaranju8185@gmail.com**

**सारांश**

प्रस्तुत अध्ययन "झारखण्ड के राँची जिले के दिव्यांगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सुधार में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की पहल" दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण एवं समावेशी विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य राँची जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकारी योजनाओं तथा गैर-सरकारी संस्थाओं (NGO) द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण करना तथा उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। किसी भी समाज का समावेशी एवं सतत विकास तभी संभव है, जब समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सहभागिता प्राप्त हो। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाएँ, पुनर्वास कार्यक्रम, कौशल विकास योजनाएँ, शिक्षा सहायता, पेंशन योजनाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनेक गैर-सरकारी संस्थाएँ भी दिव्यांगों के पुनर्वास, प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, जागरूकता एवं सामाजिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में कुल 185 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया, जिनमें 150 दिव्यांग व्यक्ति, 20 सरकारी अधिकारी तथा 15 NGO प्रतिनिधि शामिल थे। अध्ययन में मिश्रित विधि (Mixed Method) का उपयोग किया गया, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं दस्तावेज़ विश्लेषण द्वारा आँकड़ों का संग्रह किया गया। अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि Social Justice Theory, समावेशी विकास सिद्धांत, मानव अधिकार दृष्टिकोण तथा पुनर्वास मॉडल (Rehabilitation Model) पर आधारित रही। इन सिद्धांतों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास का आवश्यक अंग है।

अध्ययन में यह पाया गया कि सरकारी योजनाओं जैसे दिव्यांग पेंशन, कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा सहायता एवं रोज़गार योजनाओं ने दिव्यांग व्यक्तियों की आय एवं जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पुनर्वास कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर, जागरूकता अभियान एवं रोजगार सहायता कार्यक्रमों ने भी दिव्यांगों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में प्रभावी योगदान दिया। सारणीबद्ध विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि सरकारी योजना लाभार्थियों की आय स्तर 5000 रुपये से बढ़कर 8000 रुपये तथा NGO लाभार्थियों की आय 4800 रुपये से बढ़कर 8500 रुपये तक पहुँची। इसके अतिरिक्त रोजगार प्राप्त करने वाले दिव्यांगों का प्रतिशत 65% पाया गया तथा सामाजिक सहभागिता के स्तर में 40% से बढ़कर 70% तक की वृद्धि देखी गई। प्राप्त t-value = 5.88 ($p < 0.05$) सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सरकारी एवं NGO प्रयास दिव्यांगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हुए।

अध्ययन के निष्कर्षों से यह भी स्पष्ट हुआ कि यद्यपि सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रयासों से दिव्यांग व्यक्तियों की आय, रोजगार एवं सामाजिक सहभागिता में वृद्धि हुई है, तथापि जागरूकता की कमी, संसाधनों की सीमाएँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की अनुपलब्धता एवं प्रशिक्षण अवसरों का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अध्ययन यह संकेत देता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र विकास हेतु सरकारी योजनाओं एवं

NGO प्रयासों के मध्य बेहतर समन्वय, व्यापक जागरूकता अभियान, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार तथा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार अध्ययन यह स्थापित करता है कि सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की संयुक्त पहल दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा समावेशी एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में प्रभावी योगदान प्रदान करती है।

**कुंजी शब्द:** दिव्यांग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सरकारी योजनाएँ, NGO, पुनर्वास

## परिचय

दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी समाज के समावेशी एवं न्यायपूर्ण विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। किसी राष्ट्र की प्रगति केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को समान अवसर, सम्मान, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सहभागिता कितनी मात्रा में उपलब्ध है। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को लंबे समय तक सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यद्यपि वर्तमान समय में सरकार एवं विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, फिर भी उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता।

झारखंड के रांची जिले में भी बड़ी संख्या में दिव्यांग व्यक्ति निवास करते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को संसाधनों की कमी, जागरूकता के अभाव, सामाजिक भेदभाव एवं रोजगार के सीमित अवसरों जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग पेंशन, कौशल विकास, स्वरोजगार, शिक्षा सहायता, छात्रवृत्ति, पुनर्वास एवं सामाजिक सुरक्षा जैसी अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाएँ (NGO) भी दिव्यांगों के पुनर्वास, प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, जागरूकता अभियान एवं सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के विकास के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं होती, बल्कि सामाजिक स्वीकृति, आत्मनिर्भरता, शिक्षा एवं सम्मानजनक जीवन के अवसर भी अत्यंत आवश्यक हैं। इस दृष्टि से सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारी योजनाएँ जहाँ आर्थिक सहायता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, वहीं NGO संस्थाएँ प्रशिक्षण, परामर्श, पुनर्वास एवं सामुदायिक जागरूकता के माध्यम से दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती हैं। इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से दिव्यांग व्यक्तियों में आत्मविश्वास, रोजगार क्षमता एवं सामाजिक सहभागिता का विकास संभव होता है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राँची जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों का विश्लेषण करना है। अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम दिव्यांगों की आय, रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही यह अध्ययन उन चुनौतियों एवं बाधाओं को भी रेखांकित करता है, जो दिव्यांग सशक्तिकरण की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करती हैं। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा दिव्यांगों के समावेशी विकास हेतु प्रभावी रणनीतियों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

## अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

प्रस्तुत अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार एवं पुनर्वास से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। अध्ययन का प्रमुख आधार समावेशी विकास सिद्धांत (Inclusive Development Theory) है, जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है। यह सिद्धांत समान अवसर, सामाजिक सहभागिता एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर बल देता है। दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि में Social Justice Theory भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह सिद्धांत समाज में समानता, अधिकार एवं न्याय की स्थापना पर बल देता है। दिव्यांग व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक भेदभाव, आर्थिक निर्भरता एवं अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक न्याय सिद्धांत के अनुसार राज्य एवं समाज का दायित्व है कि वह दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार, सम्मान एवं संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। सरकारी योजनाएँ एवं NGO पहल इसी उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करती हैं।

इसके अतिरिक्त मानव अधिकार दृष्टिकोण (Human Rights Approach) भी इस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस दृष्टिकोण के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सम्मानजनक जीवन जीने का समान अधिकार प्राप्त है। United Nations द्वारा प्रतिपादित दिव्यांग अधिकार संबंधी सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि दिव्यांगता को केवल शारीरिक या मानसिक सीमा के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक समावेशन एवं अधिकारों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। अतः दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।

अध्ययन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में पुनर्वास मॉडल (Rehabilitation Model) भी महत्वपूर्ण है। इस मॉडल के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण, कौशल विकास, चिकित्सा सहायता, परामर्श एवं सामाजिक सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं सक्षम बनाया जा सकता है। सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए सरकारी योजनाओं, सामाजिक सहयोग एवं पुनर्वास प्रयासों का समन्वित एवं समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है।

## अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह झारखंड के रांची जिले में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझा जाए। यह अध्ययन दिव्यांग व्यक्तियों की आय, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सहभागिता एवं पुनर्वास से संबंधित समस्याओं तथा सुधार की संभावनाओं को स्पष्ट करता है।

अध्ययन का महत्व इस दृष्टि से भी है कि यह सरकारी योजनाओं एवं NGO प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है। अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि दिव्यांग पेंशन, कौशल विकास, पुनर्वास, रोजगार सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रम किस सीमा तक दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने में सफल हो रहे हैं। इसके माध्यम से योजनाओं की कमियों एवं चुनौतियों की पहचान कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं।

यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए भी उपयोगी है। अध्ययन के निष्कर्ष दिव्यांग सशक्तिकरण से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही यह अध्ययन समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता, समानता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि राँची जिले में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर स्थानीय स्तर पर सीमित शोध कार्य उपलब्ध हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन समावेशी विकास, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं सामाजिक योगदान प्रदान करता है।

**समस्या का विवरण**

दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा विभिन्न गैर-सरकारी संस्थाएँ भी पुनर्वास, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं रोजगार सहायता के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद अनेक दिव्यांग व्यक्ति आज भी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक उपेक्षा एवं संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता के अभाव, योजनाओं तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं एवं सामाजिक भेदभाव के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है।

रांची जिले में सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न पहलें संचालित होने के बावजूद यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि ये प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर, आय, रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक सहभागिता में किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन की समस्या यह है कि सरकारी योजनाओं एवं NGO प्रयासों के बावजूद दिव्यांगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हो पाया तथा इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों की वास्तविक प्रभावशीलता क्या है। अध्ययन का उद्देश्य इन प्रयासों की उपलब्धियों, सीमाओं एवं चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करना है।

**प्रमुख शब्दों की प्रकार्यात्मक परिभाषा**

- **दिव्यांग:** शारीरिकमानसिक अक्षमता वाले व्यक्ति/
- **सामाजिक:आर्थिक स्थिति-** आय, शिक्षा, रोजगार स्तर
- **NGO:** गैरसरकारी संगठन-

**चर**

- **स्वतंत्र चर-** सरकारी योजनाएँ, NGO पहल
- **आश्रित चर-** आय स्तर, रोजगार, सामाजिक भागीदारी, शिक्षा

**अध्ययन के उद्देश्य**

1. सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन
2. NGO की भूमिका का विश्लेषण
3. सामाजिकआर्थिक सुधार का मूल्यांकन-

## शोध प्रश्न

- क्या सरकारी योजनाएँ प्रभावी हैं?
- क्या NGO प्रयास सफल हैं?

## समस्या का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन का क्षेत्र रांची जिला है। अध्ययन में राँची जिले के दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा उनके सुधार हेतु सरकारी-सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन विशेष रूप से दिव्यांगों की आय-एवं गैर, रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक सहभागिता से संबंधित पहलुओं पर केंद्रित है।

## सीमांकन

प्रस्तुत अध्ययन 185 प्रतिभागियों तक सीमित रखा गया, जिनमें दिव्यांग व्यक्ति, सरकारी अधिकारी एवं NGO प्रतिनिधि सम्मिलित थे। अध्ययन की अवधि 3 माह निर्धारित की गई, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण, साक्षात्कार एवं दस्तावेज़ विश्लेषण के माध्यम से आँकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया गया। अध्ययन केवल राँची जिले में संचालित सरकारी एवं गैरआर्थिक प्रभावों तक सीमित है।-सरकारी पहलों तथा उनके सामाजिक-

## साहित्य समीक्षा

- UNESCO (2020) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम है, जो उन्हें आत्मनिर्भरता, सामाजिक सहभागिता एवं सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्रदान करती है। UNESCO ने विशेष रूप से तकनीकी सहायता, समावेशी शिक्षण वातावरण एवं समान अवसरों की आवश्यकता पर बल दिया।
- Government of India Report (2021) में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में यह पाया गया कि दिव्यांग पेंशन, कौशल विकास, शिक्षा सहायता एवं रोजगार योजनाओं ने दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक सुधार किया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता एवं योजनाओं की पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता है।
- Sharma (2022) ने दिव्यांग सशक्तिकरण में गैर-सरकारी संस्थाओं (NGO) की भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि NGO संस्थाएँ पुनर्वास, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं रोजगार सहायता के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उनके प्रयासों से दिव्यांगों में आत्मविश्वास, सामाजिक सहभागिता एवं आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है।
- Kumar (2023) ने पुनर्वास कार्यक्रमों की उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए पाया कि कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास सेवाएँ दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार क्षमता एवं जीवन स्तर को सुधारने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। अध्ययन के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होते हैं।
- Singh (2023) ने समावेशी विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए यह स्पष्ट किया कि समाज के सतत एवं न्यायपूर्ण विकास के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के संयुक्त प्रयासों से ही दिव्यांग व्यक्तियों का वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण संभव है।

**शोध अंतराल**

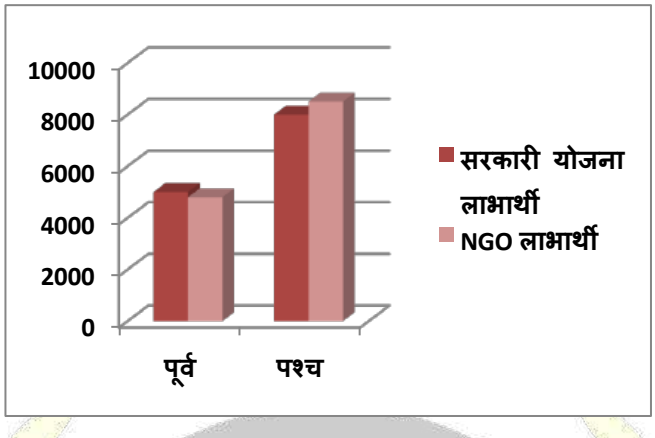
- उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण, सरकारी योजनाओं एवं NGO पहलों पर विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के अध्ययन किए गए हैं। तथापि Ranchi जिले के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति- सरकारी संस्थाओं की भूमिका का स्थानीय स्तर पर विस्तृत एवं तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित पाया-तथा सरकारी एवं गैर गया। विशेष रूप से राँची जिले में दिव्यांगों की आय, रोजगार, सामाजिक सहभागिता एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के प्रभाव का मिश्रित विधि )Mixed Method) द्वारा विश्लेषण बहुत कम किया गया है। इसी शोध अंतराल को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन स्थानीय स्तर पर सरकारी एवं NGO प्रयासों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है।
- **शोध पद्धति**
- प्रस्तुत अध्ययन में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सरकारी संस्थाओं की भूमिका का-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकारी एवं गैर- अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित शोध पद्धति का उपयोग किया गया। अध्ययन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियों का समन्वित रूप से प्रयोग किया गया, जिससे अध्ययन अधिक विश्वसनीय एवं व्यापक बन सके।
- **शोध डिज़ाइन-** प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित विधि )Mixed Method) शोध डिज़ाइन का उपयोग किया गया। इस डिज़ाइन के अंतर्गत मात्रात्मक आँकड़ों के साथसाथ गुणात्मक सूचनाओं का भी विश्लेषण किया गया-, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का समग्र अध्ययन संभव हो सका।
- **जनसंख्या-** अध्ययन की जनसंख्या में Ranchi जिले के दिव्यांग व्यक्ति सम्मिलित किए गए। अध्ययन विशेष रूप से उन व्यक्तियों पर केंद्रित रहा जो सरकारी योजनाओं एवं NGO कार्यक्रमों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे।
- **न्यादर्श-** प्रस्तुत अध्ययन हेतु कुल 185 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिनमें दिव्यांग व्यक्ति, सरकारी अधिकारी एवं NGO प्रतिनिधि सम्मिलित थे।
- **न्यादर्श विधि-** अध्ययन में यादृच्छिक न्यादर्श विधि )Random Sampling Method) का उपयोग किया गया, जिससे प्रतिभागियों के चयन में निष्पक्षता एवं समान अवसर सुनिश्चित हो सके।
- **आँकड़ों का स्रोत-** अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े प्रतिभागियों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए गए, जबकि द्वितीयक आँकड़े रिपोर्ट, दस्तावेज़, शोध पत्र एवं सरकारी अभिलेखों से संकलित किए गए।
- **शोध उपकरण-** आँकड़ों के संग्रह हेतु प्रश्नावली, साक्षात्कार एवं दस्तावेज़ विश्लेषण को शोध उपकरण के रूप में उपयोग किया गया। इन उपकरणों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा सरकारी एवं-NGO प्रयासों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई।
- **आँकड़ों का संग्रह-** अध्ययन में सर्वेक्षण एवं इंटरव्यू विधि के माध्यम से आँकड़ों का संग्रह किया गया। प्रतिभागियों से प्रत्यक्ष संवाद एवं प्रश्नावली के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त की गईं।
- **सांख्यिकीय विश्लेषण-** संग्रहित आँकड़ों के विश्लेषण हेतु Percentage, Mean एवं t-test जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग किया गया। इन तकनीकों के माध्यम से सरकारी एवं NGO प्रयासों के प्रभाव तथा सामाजिक आर्थिक सुधार की स्थिति का मूल्यांकन- किया गया।

**सारणीकरण और व्याख्या**

**सारणी 1: आय स्तर सुधार**

| समूह | पूर्व | पश्च |
|---|---|---|
| सरकारी योजना लाभार्थी | 5000 | 8000 |

| समूह | पूर्व | पश्च |
|---|---|---|
| NGO लाभार्थी | 4800 | 8500 |




**विश्लेषण**

उपरोक्त सारणी में सरकारी योजनाओं एवं गैर सरकारी-संस्थाओं )NGO) से लाभान्वित दिव्यांग व्यक्तियों के आय स्तर का पूर्व एवं पश्च तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि दोनों समूहों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकारी योजना लाभार्थियों की औसत आय 5000 रुपये से बढ़कर 8000 रुपये हो गई, जबकि NGO लाभार्थियों की औसत आय 4800 रुपये से बढ़कर 8500 रुपये तक पहुँच गई। यह दर्शाता है कि सरकारी एवं NGO दोनों प्रकार के प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रभावी रहे, किन्तु NGO समूह में आय वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक पाई गई।

**व्याख्या**

प्राप्त परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, स्वरोजगार योजनाएँ एवं पुनर्वास कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी योजनाओं ने आर्थिक सहायता, पेंशन एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, जबकि NGO संस्थाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार अवसर, जागरूकता एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से उनकी आय क्षमता को अधिक प्रभावी रूप से विकसित किया। NGO लाभार्थियों की आय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि यह संकेत देती है कि स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष सहयोग, व्यक्तिगत परामर्श एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हुए। इस प्रकार अध्ययन यह स्थापित करता है that सरकारी एवं NGO दोनों के संयुक्त प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।

**सारणी 2: रोजगार स्थिति**

| स्थिति | प्रतिशत |
|---|---|
| रोजगार प्राप्त | 65% |
| बेरोजगार | 35% |

**विश्लेषण**

उपरोक्त सारणी में अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित दिव्यांग व्यक्तियों की रोजगार स्थिति का प्रतिशत आधारित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि कुल प्रतिभागियों में से 65% दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ, जबकि 35% प्रतिभागी अभी भी बेरोजगार पाए गए। यह आँकड़ा दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं एवं NGO प्रयासों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार स्तर में सकारात्मक सुधार हुआ है, तथापि अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रतिशत रोजगार से वंचित है।

**व्याख्या**

प्राप्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि कौशल विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास सेवाएँ एवं रोजगार सहायता योजनाएँ दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने दिव्यांगों- की कार्य क्षमताएवं आत्मनिर्भरता को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को रोजगार प्राप्त हुआ। तथापि 35% प्रतिभागियों का बेरोजगार रहना यह संकेत देता है कि जागरूकता की कमी, सीमित रोजगार अवसर, सामाजिक भेदभाव, संसाधनों की अनुपलब्धता एवं पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अतः दिव्यांग व्यक्तियों के पूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण हेतु रोजगार उन्मुख योजनाओं एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

**सारणी 3: सामाजिक भागीदारी**

| संकेतक | पूर्व | पश्च |
|---|---|---|
| सहभागिता | 40% | 70% |




**विश्लेषण**

उपरोक्त सारणी में दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक भागीदारी का पूर्व एवं पश्च तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणामों से स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि के दौरान सामाजिक सहभागिता के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पूर्व स्थिति में सामाजिक भागीदारी का स्तर 40% था, जो सरकारी योजनाओं एवं NGO पहलों के पश्चात बढ़कर 70% हो गया। यह अंतर दर्शाता है कि विभिन्न पुनर्वास, जागरूकता एवं सामाजिक समावेशन कार्यक्रमों ने दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## व्याख्या

प्राप्त निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित जागरूकता अभियान-, प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक गतिविधियाँ एवं पुनर्वास सेवाएँ दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं। इन पहलों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों में आत्मविश्वास, सामाजिक स्वीकृति एवं सहभागिता की भावना विकसित हुई, जिससे वे सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने लगे। सामाजिक भागीदारी में वृद्धि यह संकेत देती है कि समावेशी विकास एवं सामाजिक समर्थन के प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों को अलगाव एवं उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकालकर उन्हें सम्मानजनक एवं सहभागी जीवन की ओर अग्रसर कर रहे हैं।

## परिकल्पना परीक्षण

अध्ययन में प्राप्त t-value = 5.88 तथा $p < 0.05$ पाया गया, जो सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्राप्त t-value निर्धारित सारणी मान से अधिक होने के कारण यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं एवं गैर) सरकारी संस्थाओं-NGO) द्वारा किए गए प्रयासों का दिव्यांग व्यक्तियों की सामाजिक) आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अतः शून्य परिकल्पना-$H_0$) अस्वीकृत तथा वैकल्पिक परिकल्पना )$H_1$) स्वीकृत की जाती है।

## निष्कर्ष

प्राप्त परिणाम यह सिद्ध करते हैं कि सरकारी एवं NGO प्रयास दिव्यांग व्यक्तियों की आय, रोजगार, सामाजिक सहभागिता एवं जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हुए हैं। कौशल विकास कार्यक्रम, पुनर्वास सेवाएँ, रोजगार सहायता, जागरूकता अभियान एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर एवं सामाजिक रूप से अधिक सहभागी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्ययन यह भी संकेत देता है कि सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं के संयुक्त एवं स-मन्वित प्रयास समावेशी विकास एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत आवश्यक एवं प्रभावी हैं।

## अनुशंसाएँ

- दिव्यांग व्यक्तियों एवं उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं, पुनर्वास सेवाओं, शिक्षा एवं रोजगार अवसरों के प्रति जागरूक करने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान संचालित किए जाने चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सूचना की पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग व्यक्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
- दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी एवं रोजगारोन्मुख बनाया जाना चाहिए। सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं को तकनीकी प्रशिक्षण-, स्वरोजगार सहायता एवं रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में समन्वित प्रयास करने चाहिए।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे सहायक उपकरण, प्रशिक्षण केंद्र, पुनर्वास सेवाएँ, डिजिटल सुविधाएँ एवं आर्थिक सहायता की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही सरकारी योजनाओं एवं NGO कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आधारभूत संरचना एवं वित्तीय संसाधनों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

## संदर्भ

- यूनेस्को। (2020). *दिव्यांग शिक्षा एवं समावेशी अधिगम पर वैश्विक रिपोर्ट*। पेरिस: यूनेस्को पब्लिशिंग।

- भारत सरकार। (2021). *दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट*। नई दिल्ली: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- शर्मा, आर. (2022). *दिव्यांग सशक्तिकरण में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका: एक अध्ययन*। नई दिल्ली: रावत पब्लिकेशन्स।
- कुमार, एस. (2023). *पुनर्वास कार्यक्रम एवं दिव्यांग व्यक्तियों का सामाजिक-आर्थिक विकास*। पटना: ओरिएंट पब्लिशिंग हाउस।
- सिंह, पी. (2023). *समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय: दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में*। जयपुर: वाणी प्रकाशन।